



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 298]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 24, 2019/आश्विन 2, 1941

No. 298]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 24, 2019/ASVINA 2, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2019

(मामला सं. 15/2019)

विषय: : मलेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित इलैक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

फा. सं. 6/22/2019 – डी जी टी आर.— यतः मै. अजंता एल एल पी (जिसे पहले मै. अजंता प्राइवेट लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता था) (जिसे आगे आवेदक कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे यहां अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण एवं क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे यहां इसके बाद नियमावली भी कहा गया है) के अनुसरण में घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें यहां इसके बाद प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है। जिसमें मलेशिया (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित इलैक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स (जिसे आगे संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के पाटन का आरोप लगाया है और संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने और पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

- और यतः प्राधिकारी संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति और पाटन तथा क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य पाते हैं और एतद्वारा पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति के संबंध में जांच की शुरूआत करते हैं ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क

की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी। मै. अजंता एल एल पी (जिसे आगे आवेदक या याचिकाकर्ता कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे यहां आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण एवं क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे यहां इसके बाद नियमावली भी कहा गया है) के अनुसरण में निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें यहां इसके बाद प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है। जिसमें मलेशिया से इलैक्ट्रॉनिक कैलकुलेटरों (जिसे आगे संबद्ध वस्तु या पीयूसी भी कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

विचाराधीन उत्पाद

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद इलैक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर है। इलैक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर एक छोटा और पोर्टेबल इलैक्ट्रॉनिक यंत्र होता है जिसका प्रयोग अंकगणित प्रचालनों और कतिपय अन्य गणितीय कार्यों को करने के लिए किया जाता है। सरल संख्यात्मक प्रचालनों में मूलभूत अंकगणित जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग शामिल हैं, जटिल गणितीय कार्यों में एक्सपोनेंशियल प्रचालन, वर्गमूल, लागेरिथम, त्रिकोणमिती कार्य और हाइपरबोलिक कार्य आदि शामिल हैं और इसमें इसके सभी वाणिज्यिक/व्यापार शब्दावली वाले नाम शामिल हैं।
4. वर्तमान जांच के लिए विचाराधीन उत्पाद "सभी प्रकार के इलैक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर" हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं।
 - क. कैलकुलेटर जिनके साथ प्रिंटर लगा हो, जिन्हें आम तौर पर प्रिंटिंग कैलकुलेटर कहा जाता है।
 - ख. कैलकुलेटर जो चार्ट और ग्राफ बना सकते हों, जिन्हें आम तौर पर ग्राफिंग कैलकुलेटर कहा जाता है।
 - ग. प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर
5. विचाराधीन उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की टैरिफ मद 84701000 के अधीन वर्गीकृत किया जाता है।

समान वस्तु

6. समान वस्तु के संबंध में नियम 2(घ) में निम्नानुसार व्यवस्था है :-

"समान वस्तु" से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटन के कारण जांच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरूप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जोकि यद्यपि सभी प्रकार से समरूप नहीं है परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं;
7. आवेदक ने कहा है कि उनके द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु समान वस्तुएं हैं। संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध वस्तु और आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। आवेदक द्वारा उत्पादित इलैक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर और संबद्ध देशों से आयातित इलैक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर तकनीकी विशेषताओं, कार्य और प्रयोग, वितरण एवं विपणन, कीमत निर्धारण और टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय है। याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं और संबद्ध देशों से वस्तुएं संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं और याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित वस्तुओं के बीच घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुएं और संबद्ध देशों से आयातित वस्तुएं अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं जैसे भौतिक और रसायनिक विशेषताएं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं प्रयोग, उत्पाद विशिष्टताएं, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की शर्तों में तुलनीय हैं। उपभोक्ता दोनों को प्रतिस्थापनीय रूप से प्रयोग कर सकते हैं और कर रहे हैं। दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए नियमों के अंतर्गत उन्हें "समान वस्तु" माना जाना चाहिए। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है।

घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

8. यह आवेदन मै. अजंता एलएलपी, जो भारत में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादक हैं द्वारा दायर किया गया है। उपलब्ध सूचना से प्राधिकारी प्रथमदृष्टया नोट करते हैं कि घरेलू उत्पादक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु का उत्पादन भारत में विचाराधीन उत्पाद के कुल उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता है। अतः प्राधिकारी प्रथम दृष्टया निर्धारित करते हैं कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग हैं और आवेदन नियमावली के नियम 5(3) की शर्तों के भीतर योग्यता संबंधी मापदंडों को पूरा करते हैं।

शामिल देश

9. वर्तमान जांच मलेशिया से पीयूसी के कथित पाटन के संबंध में है।

सामान्य मूल्य

10. आवेदक ने यह बताते हुए संबद्ध देश के संबंध में सामान्य मूल्य की गणना की है कि न तो वे संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु की घरेलू कीमतों के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य या विश्वसनीय सूचना प्राप्त करने में सक्षम रहे, न ही वह सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है। प्राधिकारी ने प्रथमदृष्टया इस जांच शुरुआत के प्रयोजनार्थ आवेदक द्वारा यथाउपलब्ध परिकलित मूल्यों के आधार पर संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य पर विचार किया है।

निर्यात कीमत

11. आवेदक ने डी जी सी आई एंड एस, कोलकाता द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर संबद्ध देश से निर्यात कीमत का परिकलन किया है। समुद्री भाड़ा, अंतर्देशीय माल भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन और बैंक प्रभारों के कारण कीमत समायोजन का दावा किया गया है। आवेदकों द्वारा दावा की गई निवल निर्यात कीमतों के संबंध में पर्याप्त प्रथम दृष्टया प्रमाण हैं।

पाटन मार्जिन

12. संबद्ध देश के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की कारखाना द्वार स्तर पर तुलना की गई है जो प्रथमदृष्टया संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के संबंध में उल्लेखनीय भारी पाटन मार्जिन को दर्शाता है। इसके प्रथम दृष्टया प्रमाण हैं कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखाना द्वार निर्यात कीमत की तुलना में अधिक है जो प्रथम दृष्टया दर्शाता है कि संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु पाटित की जा रही हैं।

क्षति और कारणात्मक संबंध

13. आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना पर घरेलू उद्योग की क्षति के आकलन के लिए विचार किया गया है। आवेदकों ने कुल रूप में पाटित आयातों की बढ़ी हुई मात्रा के रूप में कथित पाटन के परिणामस्वरूप सामना की गई क्षति तथा भारत में उत्पादन और खपत, कीमत में कटौती, कम कीमत पर बिक्री, लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। एक पाटनरोधी जांच की शुरुआत का औचित्य सिद्ध करने के लिए संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण उत्पन्न घरेलू उद्योग द्वारा सामना की जा रही "क्षति" के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं।

पाटनरोधी जांच की शुरुआत

14. और जबकि प्राधिकारी ने प्रथमदृष्टया यह पाया है कि पाटनरोधी जांच की शुरुआत का औचित्य सिद्ध करने के लिए संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति, उद्योग के क्षति एवं कथित पाटन और क्षति के बीच मौजूद कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य हैं, प्राधिकारी कथित पाटन की

विद्यमानता, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की मात्रा की सिफारिश करने, जो यदि लागू होता तो घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होता, एतद्वारा पाटनरोधी नियमावली 1995 के नियम 5 की शर्तों में कथित पाटन और घरेलू उद्योग की परिणामी क्षति की जांच की शुरुआत करते हैं।

जांच की अवधि

15. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि (जिसे आगे पीओआई कहा गया है) 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 (12 माह) की है। तथापि, क्षति जांच अवधि में पिछले 3 वर्षों अर्थात् अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016, अप्रैल, 2016 से मार्च, 2017, अप्रैल, 2017 से मार्च, 2018 और पीओआई की अवधियां शामिल होंगी।

सूचना प्रस्तुत करना

16. संबद्ध देश में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकार, भारत में उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों व प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना उपलब्ध कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है।
17. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत कोई अनुरोध नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है। सूचना/अनुरोध निम्नलिखित को प्रस्तुत की जा सकती है :

निर्दिष्ट प्राधिकारी

व्यापार उपचार महानिदेशालय

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

भारत सरकार

चौथा तल ,जीवन तारा बिल्डिंग,

5 संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

18. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षों को उसे उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश भी प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

समय-सीमा

19. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (दिनों **40**) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
20. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जांच की शुरुआत अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से **40** दिनों के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें। मूल प्रतियों और सॉफ्ट प्रतियों में अवश्य प्रस्तुत की जानी चाहिए।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

21. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए उसके किसी भाग के संबंध में "गोपनीयता" का दावा करने के मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा:-

- i. गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक ,सूची ,पृष्ठ संख्या आदि); और
 - ii. अगोपनीय रूप में अंकित दूसरा सैट (शीर्षक ,सूची ,पृष्ठ संख्या आदि)।
22. "गोपनीय "या" अगोपनीय "अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। दोनों पाठों की हार्ड कॉपियों के साथ साफ्ट कॉपियां चार (4) सैट में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।
 23. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
 24. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना ,जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है ,पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि ,आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।
 25. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
 26. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
 27. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

28. नियमावली के नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

असहयोग

29. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th September, 2019

[Case No: 15/2019]

Subject: Initiation of Anti-dumping investigation concerning imports of Electronic Calculators originating in or exported from Malaysia.

F. No. 6/22/2019-DGTR.—Whereas M/s. Ajanta LLP (formerly known as M/s. Ajanta Private Limited) (hereinafter referred to as the “Applicant”) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority), on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as the “Act”) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the “Rules”), alleging dumping of Electronic Calculators (hereinafter referred to as the “subject goods”), originating in or exported from Malaysia (hereinafter referred to as the “subject country”), for initiation of anti-dumping investigation and for levy of anti-dumping duty on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.

2. AND WHEREAS, the Authority finds sufficient prima facie evidence of dumping of the subject goods, originating in or exported from subject country, and injury to the domestic industry, and causal link between the dumping and injury and hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of the Rule 5 of the Anti-dumping Rules, to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry. M/s. Ajanta LLP (hereinafter also referred to as the “Petitioner” or “Applicant”) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the “Rules”) for imposition of anti-dumping duty on imports of Electronic Calculators (hereinafter referred to as the “subject goods” or “PUC”) from Malaysia.

Product under consideration

3. The product under consideration in the present investigation is Electronic Calculators. An electronic calculator is a small and portable electronic device used for performing arithmetic operations and certain other mathematical functions. Simple numeric operations include basic arithmetic such as addition, subtraction, multiplication and division. Complex mathematical functions include exponential operations, roots, logarithms, trigonometric functions, and hyperbolic functions, etc. and include all its commercial/trade parlance names.
4. The product under consideration for the present investigation is ‘Electronic Calculators of all types’, *excluding* the following:
- a. Calculators with attached printers, commonly referred to as *printing calculators*
 - b. Calculators with ability to plot charts and graphs, commonly referred to as *graphing calculators*
 - c. *Programmable calculators*
5. The product under consideration is classified under tariff item 8470 1000 of the Customs Tariff Act, 1975.

Like Article

6. Rule 2(d) with regard to like article provides as under: -

"like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation;

7. The Applicant has submitted that the subject goods produced by them and the subject goods imported from the subject country are like articles. There is no known difference between the subject goods exported from the subject country and those produced by the Applicant. Electronic Calculators produced by the Applicant and imported from the subject countries are comparable in terms of technical characteristics, functions and uses, distribution and marketing, pricing and tariff classification. Consumers can use and are using the two interchangeably. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as 'like article' under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the Applicant are being treated as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject country.

Domestic industry and Standing

8. The application has been filed by M/s. Ajanta LLP, the producer of the product under consideration in India. From the available information, the Authority prima facie notes that the production of subject goods produced by the domestic producer accounts for "a major proportion" of total production of the product under consideration in India. The Authority, therefore, prima facie determines that the Applicant constitutes domestic industry within the meaning of the Rule 2 (b) of Rules, and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Rules.

Country Involved

9. The present investigation is in respect of alleged dumping of the PUC from Malaysia.

Normal Value

10. The Applicant has constructed the normal value in respect of subject country stating that neither they were able to get any documentary evidence or reliable information with regard to domestic prices of the subject goods in the subject country nor the same are available in the public domain. The Authority has prima-facie considered the normal value of subject goods in subject country on the basis of constructed values as made available by the Applicant for the purpose of this initiation.

Export Price

11. The Applicant has computed the export price for the subject country on the basis of data published by DGCI&S, Kolkata. Price adjustments have been claimed on account of ocean freight, inland freight, ocean insurance, commission and bank charges. There is sufficient prima facie evidence with regard to the net export prices claimed by the Applicant.

Dumping Margin

12. The normal values and the export prices for the subject country has been compared at ex-factory level, which prima facie show significant dumping margins in respect of the subject goods exported from the subject country. There is sufficient prima facie evidence that the normal values of the subject goods in the subject country were higher than the ex-factory export prices, indicating that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject country.

Injury & Causal Link

13. Information furnished by the Applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The Applicant has furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports in absolute terms and in relation to production and consumption in India, price undercutting, price underselling, profitability, cash profits and return on capital employed. There is sufficient prima facie evidence of injury being suffered by the domestic industry caused by dumped imports from the subject country to justify initiation of an anti-dumping investigation.

Initiation of Anti-Dumping Investigation

14. And whereas, the Authority prima facie finds that there is sufficient evidence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject country; and injury to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and injury exists to justify initiation of an anti-dumping investigation, the Authority hereby

initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of Rule 5 of the Anti-Dumping Rules 1995, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the 'injury' to the domestic industry.

Period of Investigation

15. The period of investigation (hereinafter referred to as "POI") for the present investigation is from 1st April 2018 to 31st March 2019 (12 months). The injury investigation period will, however, cover the periods April 2015-March 2016, April 2016-March 2017, April 2017-March 2018 and the POI.

Submission of information

16. The known exporters in the subject country and their government through their embassy in India, importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
17. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below. The information/submission may be submitted to:

The Designated Authority
Directorate General of Trade Remedies
Ministry of Commerce & Industry
Department of Commerce
Government of India
4th Floor, Jeevan Tara Building, 5, Parliament Street
New Delhi-110001

18. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

Time-Limit

19. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 days) from the date of the publication of this initiation notification. If no information is received within the prescribed time-limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.
20. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application within forty days (40 days) from the date of the publication of this initiation notification. The information must be submitted in hard copies as well as in soft copies.

Submission of information on confidential basis

21. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof:
 - i. One set marked as Confidential (with title, number of pages, index, etc.), and
 - ii. The other set marked as Non-Confidential (with title, number of pages, index, etc.).
22. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect

such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies, in four (4) sets of each.

23. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
24. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarised depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarisation is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
25. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in generalised or summary form, it may disregard such information.
26. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
27. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorisation of the party providing such information.

Inspection of Public File

28. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

29. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Designated Authority